भजनलाल कैबिनेट ने राज्य में औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति बनाई

दो से अधिक संतान वाले पंचायत व नगरपालिका चुनाव लड़ सकेंगे, राजस्व अपराध निदेशालय बनेगा

जयपुर, 25 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को विधानसभा सचिवालय में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026 और राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026 लाने, राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए।

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कैबिनेट बैठक के बाद विधानसभा में आयोजित प्रेसवार्ता में बताया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-19 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा-24 में संशोधन कर राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026 और राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026 लाने का महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है। इससे जिन व्यक्तियों के दो से अधिक संतान हैं वे पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरपालिकाओं के चुनाव लड़ सकेंगे। उन्होंने बताया कि दो से अधिक संतान पर चुनाव लड़ने का प्रतिबंध उस समय लागू किया गया था, जब जनसंख्या विस्फोट पर प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता थी।

डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि आर्थिक अपराधों पर प्रभावी रोकथाम तथा वित्तीय अनुशासन के लिए राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय को समाप्त कर राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन का निर्णय मंत्रिमण्डल में किया गया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में जयपुर में राजस्थान मंडपम, ग्लोबल कैपेबिलिटी सैंटर के नए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें राज्य सरकार के 635 करोड़ रूपए खर्च नहीं होंगे, बल्कि संशोधित मॉडल में 10 करोड़ रूपए की शुद्ध आय होगी।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया औद्योगिक विकास को नई गति देने, निवेश को प्रोत्साहित करने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने तथा सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति, 2026 लाई जाएगी।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने यह भी बताया कि मंत्रिमण्डल की बैठक में आज संशोधित वित्तीय मॉडल का अनुमोदन किया गया। जिसके अंतर्गत परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 5 हजार 815 करोड़ रुपए तथा अनुमानित राजस्व प्राप्ति 5 हजार 825 करोड़ रुपये है। इस संशोधित मॉडल में लगभग 10 करोड़ रुपए की शुद्ध आय भी संभावित है। इसमें अब राज्य सरकार पर पूर्व में अनुमानित 635 करोड़ का वित्तीय दायित्व भी नहीं रहेगा।

झारखंड ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गया था। हेमंत सोरेन के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि सोरेन तीन बार ईडी के सामने पेश हुए, लेकिन हर बार उन्हें हिरासत में ले लिया गया। तब कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर गहरी नज़र रखी जानी चाहिए।

इस मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से जारी समन को बरकरार रखा था। उच्च न्यायालय के इसी फैसले को हेमंत सोरेन ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।

ज्ञातव्य है कि ईडी ने 31 जनवरी, 2024 को हेमंत सोरेन से पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। सोरेन को भूमि घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले हेमंत सोरेन ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया था।

'फर्ज़ी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

1989 में विश्वविद्यालय ने उन्हें तीन साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। सजा स्वीकार करने के बजाय, जहांगीरी ने धोखाधड़ी का सहारा लिया।

अगले वर्ष उन्होंने फिर से "तारिक जहांगीरी" नाम से परीक्षा दी और उस नामांकन संख्या का उपयोग किया, जो किसी अन्य छात्र, इम्तियाज़ अहमद को दी गई थी।

भारत द्वारा रूसी ऑयल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कि रूस से भारत की तेल खरीद में कमी आने से वहाँ स्टॉक जमा हो गया है।

इस बीच, रूस से कम तेल खरीद के कारण वनेज़ुएला के तेल की अधिक बुकिंग की जा रही है। भारत के निजी रिफाइनर, जिनमें दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनर रिलायंस भी शामिल हैं, वनेज़ुएला का तेल बड़े पैमाने पर अधिक मात्रा में और भारी छूट पर बुक कर रहे हैं। वनेज़ुएला का कच्चा तेल अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों से 15 डॉलर कम पर बिक रहा है। अन्य भारतीय रिफाइनर भी इस कम कीमत पर वनेज़ुएला का कच्चा तेल खरीद रहे हैं, जिनमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एचपीसीएल, मित्तल एनर्जी और भारत पेट्रोलियम शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक, कुछ बहुत बड़े कच्चे तेल वाहक वनेज़ुएला के कच्चे तेल के परिवहन के लिए बुक किए जा रहे हैं। अमेरिका अपनी तेल कंपनियों पर वनेज़ुएला के कच्चे तेल को विश्व के बाजारों में बेचने के लिए दबाव डाल रहा है, ताकि ईरान और रूस पर दबाव डाला जा सके। रूस और ईरान पर अमेरिकी शुल्क और प्रतिबंधों के कारण, उनका कच्चा तेल अंतरराष्ट्रीय मानक कीमतों से कम कीमत पर बिक रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, रूसी उरल ग्रेड 12 ब्रेंट क्रूड से नीचे बिक रहा है, जो मानक बेंचमार्क कीमत है। ईरानी कच्चा तेल वैश्विक कीमत से 11 डॉलर की छूट पर बिक रहा है। अब जबकि भारत अमेरिकी वाणिज्य विभाग के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है, यह रूस के कच्चे तेल की खरीद से दूर होता दिखाई दे रहा है। भारत की रूस से तेल खरीद पिछले साल के अंत में चरम पर थी और हाल ही में इसमें कुछ बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। कच्चा तेल जो पहले भारत आता था, अब उसे सिंगापुर और पूर्वी देशों की ओर मोड़ा जा रहा है। इसके अलावा, ईरानी तेल टैंकर भी समुद्र में हैं, क्योंकि देश अमेरिका से सीधे हमले का डर महसूस कर रहा है, क्योंकि आपूर्ति लाइनों को पूरी तरह से बंद किया जा सकता है और जहाजों की आवाजाही रुक सकती है। ईरान जितना संभव हो सके उतना तेल समुद्र में उतारने की कोशिश कर रहा है। अनुमान के मुताबिक, ईरानी तेलों का 48 मिलियन बैरल तक का भंडार समुद्र में है।

- वैसे भी समुद्र में ऑयल से भरे टैंकर्स का इस तरह से विचरण करना भी खतरे से खाली नहीं है। कोई दुर्घटना कभी भी विकराल रूप धारण कर सकती है।
- यह स्थिति भारत के लिए अधिक संकट की इसलिए भी है कि ऑयल से भरे टैंकर्स सबसे ज्यादा हिंद महासागर में मंडरा रहे हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑयल कंज़्यूमर में तीसरे नंबर पर है तथा पाकिस्तान, अफगानिस्तान व अन्य एशियाई देश, जैसे सिंगापुर भी अपनी खपत का अधिकतम ऑयल आयात ही करते हैं।

'मैं किसी को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जानकारी दी गई है। यह तर्क दिया गया कि जवाबदेही पर चर्चा महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर विशेष रूप से जोर देना, और राज्य के अन्य अंगों के बारे में वैसी ही चर्चा न करना, एकतरफा धारणा बना सकता है। पीठ के सदस्यों ने यह भी कहा कि सन्दर्भित पाठ्य सामग्री की प्रस्तुति संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं लगती, खासकर उस सिद्धांत के संदर्भ में, जो संविधान की मूल संरचना के तहत न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करता है।

बताया गया है कि पाठ्यपुस्तक के अध्याय में लंबित मामलों की संख्या, न्यायाधीशों की कमी और व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। लेकिन अदालत के हस्तक्षेप से यह स्पष्ट होता है कि शैक्षिणक सामग्री में संवेदनशील संस्थागत विषयों को सावधानी से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि आलोचनात्मक चर्चा संस्था की गरिमा को ठेस न पहुंचाए।

अब यह मामला संवैधानिक महत्व का बन गया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि न्यायपालिका की गरिमा और अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए, खासकर उन सामग्रियों में, जो किशोरों की सोच का निर्माण करती हैं।

पूर्व प्र.मंत्री शेख हसीना ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और अदालतों में चल रहे मामलों के कारण बुरी तरह से टूट चुकी है। हसीना की उम्र 78 वर्ष है और वे और उनका बेटा साजीब वाजेद जॉय, दोनों बांग्लादेश से बाहर रह रहे हैं। और जाहिर है, नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान की बीएनपी शायद ही अवामी लीग को राजनीतिक जगह देने के लिए तैयार हो। तो सवाल यह है: हसीना अपनी वापसी की संभावना के संकेत देकर आखिर क्या हासिल करना चाहती हैं?

एक परिणाम साफ नजर आ रहा है। हसीना द्वारा अपनी वापसी के संकेत दिए जाने के बाद, अवामी लीग के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में ऊर्जा भर गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कार्यकर्ता विभिन्न जिलों में पार्टी कार्यालयों के ताले तोड़कर अंदर घुसे हैं। हसीना की वापसी के घोषणा करने वाले बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं।

सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि हसीना तुरंत लौटने का इरादा नहीं रखतीं, लेकिन उनका उद्देश्य अपने बेटे साजीब वाजेद जॉय को अपना राजनैतिक उत्तराधिकारी बनाने में मदद करना हो सकता है। जॉय ने हसीना सरकार में वर्षों तक आईसीटी सलाहकार के रूप में काम किया था और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास, आईटी-आधारित प्रशासन और आधुनिकीकरण की पहल में योगदान दिया था।

उनकी "डिजिटल बांग्लादेश" योजना काफी सराही गई थी, हालांकि उनमें पार्टी राजनीति और संगठनात्मक मामलों के अनुभव की कमी है। जॉय वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं। यह संभव है कि वे नए अवामी लीग नेता के रूप में बांग्लादेश लौट आयें।

- अतः, शेख हसीना अपने वापस लौटने का संदेश प्रचारित करके क्या हासिल करना चाह रही हैं। एक कयास है कि 78 वर्षीय शेख हसीना खुद को स्थापित करने के बजाय अपने पुत्र साजीब वाजेद जॉय के अमेरिका से लौटने व बांग्लादेश में राजनीतिक नेतृत्व संभालने के लिए जमीन तैयार कर रही हैं।

ईडी ने अनिल अंबानी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ज्यादा हो गई है। ईडी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबाआई) की एफआईआर के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरसीओएम), अनिल अंबानी और दूसरों के खिलाफ जांच शुरू की थी। ईडी ने बताया कि आरसीओएम और उसकी ग्रुप कंपनियों ने लोन लिया था, जिसमें से कुल 40,185 करोड़ रुपये बकाया है। जांच में पता चला है कि दूसरी एसेट्स के अलावा, पाली हिल प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में मिला दिया गया था, जो अनिल अंबानी के परिवार के सदस्यों का एक प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट है। ईडी ने बताया कि ऐसा इसलिए किया गया, ताकि ऐसा लगे कि अनिल अंबानी इसमें शामिल नहीं हैं। फिलहाल मामले की छानबीन ईडी की टीम कर रही है।

'केरल तो ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

शब्दों का क्या होगा, जो नए "केरलम" के "निवासियों" के लिए इस्तेमाल होते थे। उन्होंने यह भी कहा कि 'केरलमाइट' किसी जीवाणु जैसा लगता है और केरलमियन किसी दुर्लभ खनिज जैसा।

इंटरनेशनल फिल्म ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर्यटन, प्रतिभा विकास, एवीजीसी, रचनात्मक उद्योग और रोजगार सृजन के नए अवसर प्रदान करेगा। फिल्म फेस्टिवल में 125 से अधिक भारतीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही गाला प्रीमियर, मास्टरक्लास, इंडस्ट्री संवाद, कार्यशालाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे।

पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली का अब तक का पहला अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित होने जा रहा है। इस महोत्सव में देश-विदेश के प्रतिष्ठित फिल्मकार, कलाकार, निर्देशक और तकनीकी विशेषज्ञ भाग लेंगे। यह महोत्सव न केवल भारतीय सिनेमा की विविधता और सृजनात्मकता को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करेगा, बल्कि दिल्ली को सशक्त फिल्म और सांस्कृतिक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

'दिल्ली ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नामों को फिर से बहाल किया है और दिल्ली का नाम बदलना राजधानी को भारत की प्राचीन धरोहर से फिर से जोड़ने की दिशा में एक कदम होगा।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालयः सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोनः 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोनः 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोनः 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालयः आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालयः राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोनः 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्सः 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600